दिनांक 08.02.2013 को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दक्षिण बिहार के प्रमंडल अवस्थित जिलों के विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग की

पत्रांक - 140415 दिनांक 28/02/2013
ग्रा.वि.अनु.को-18/2009

कार्यवाही :-

सामान्य अनुदेश 1.(मनरेगा)

- सभी जिलो को यह बताया गया की दिनांक 02 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित मनरेगा सम्मेलन में बिहार द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का प्रस्तुतीकरण नई दिल्ली नही भेजा गया। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी जिले अगले मनरेगा सम्मेलन हेतु अपने जिले मे किये जा रहे उत्कृष्ट कार्य से संबंधित सूचना, मंत्रालय द्वारा भेजे गये प्रपत्र में ससमय भेजेगें ।
- श्रम बजट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पटना, बाँका, पूर्वी चम्पारण, दरंभगा, समस्तीपुर, सुपौल, शिवहर, सहरसा, मुंगेर एवं मुजफ्फरपुर को छोडकर सभी जिलों के द्वारा अव्यवहारिक रूप से बहुत अधिक श्रम बजट अपलोड किया गया है जिससे संपूर्ण राज्य का श्रम बजट 8500 करोड रूपये प्रदर्शित हो रहा है जबकि किसी भी वित्तीय वर्ष में इतनी राशि खर्च नही की गई है । सभी जिलों को यह निदेश दिया गया कि पुनः श्रम बजट का प्रखंडवार समीक्षा कर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में श्रृजित मानव दिवस का औसत निकालकर उसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि कर तीन दिनों के अंतर्गत अपलोड किया जाय ।
- सभी जिलो को निदेश दिया गया कि मनरेगा दिवस जाँच का अद्यतन प्रतिवेदन अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय । सभी जिलो को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि योजनाओं के अभिलेख संबंधित कार्यकारी एजेंसी के पास रखा जाना सुनिश्चित किया जाय यथा पंचायत के अभिलेख पंचायत कार्यालयों में, पंचायत समिति के अभिलेख प्रखंड कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगें।
- सभी जिलो को यह निर्देश दिया गया कि IL & FS एवं BIPARD के माध्यम से दिये जा रहे प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण संबंधित जिलो के निदेशक NEP एवं निदेशक लेखा करेंगें एवं उसका प्रतिवेदन विभाग को प्रतिवेदित करेंगें ।
- सभी जिलो के द्वारा मनरेगा कर्मियों के मानदेय के भुगतान के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश की पृच्छा की गयी। तदनुरूप सभी जिलो को निदेश दिया गया कि मनरेगा कर्मियों को निर्बाध रूप से प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किया जाय । जिन मनरेगा कर्मियों का पिछले वित्तीय वर्ष का मानदेय लंबित है, उनका भी भुगतान यथाशीघ्र किया जाय । इस संबंध मे CPSMS के माध्यम से राशि प्राप्त करने हेतु एडवाइस भेजे जाय ।
- मनरेगा कर्मियो का डाटा बेस बनाकर तैयार रखने का निर्देश दिया गया ताकि विभाग द्वारा की जानेवाली नियुक्ति प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जा सके ।

सामान्य अनुदेश 2.(इंदिरा आवास योजना ।)

इंदिरा आवास के अंतर्गत लंबित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया । सभी जिलो को निदेश दिया गया कि द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु डाटाबेस बनाकर अपलोड करने की कर्रवाई मे गति लायी जाय ।

सामान्य अनुदेश 3.(सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011)

सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया कि एक्जक्युटिव असिसटेंट की बहाली यथाशीघ्र की जाय ताकि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना के कार्य मे तेजी लायी जा सके । जहाँ-जहाँ प्रगणन का कार्य पूर्ण हो चूका है वहाँ पडे अतिरिक्त टैबलेट पी0सी0 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना को वापस किया जाय ताकि आवश्यकतानुसार उसे अन्य जिलों को भेजा जा सके ।

DEO के लंबित भुगतान के संबंध में ECIL के State Co-ordinator से विभाग द्वारा वार्ता की गई है तथा इसे शीघ्र भुगतान करने का निदेश दिये गये है।

कैमूर:- जिला के द्वारा यह बताया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर Realistic श्रम बजट अपलोड कर दिया जायेगा । उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया की इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 करोड रूपये सहित कुल 30 करोड रूपये व्यय किये जाने का अनुमान है ।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिले के द्वारा यह बताया गया की उनके यहां कुल लक्ष्य में से केवल 242 लक्ष्य अवशेष है जिनमे 121 भूमिहीन, 86 बाहर तथा 12 विवादित है । जिले में केवल 2.65 करोड राशि अवशेष है जिसे सप्ताहिक कैंपो में वितरित कर लिया जायेगा । मोहनिया, रामगढ, एवं रामपुर प्रखंडों में राशि अवशेष है जहां विशेष रूप से कैंप आयोजित कर सहायता राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है । 2005-06 से 2011-12 तक के इंदिरा आवास के लाभार्थियों के सूची का डाटाबेस बन जाने की सूचना जिले के द्वारा दी गयी ।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के अंतर्गत रामगढ प्रखंड में Supervisory module का कार्य नही पूरा हुआ है क्योंकि भेंडर के द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो को मानदेय का भुगतान नही किया गया है ।

रोहतास:- जिला के द्वारा यह बताया गया कि Realistic Labour Budget तीन दिनों के अंतर्गत अपलोड कर दिया जायेगा । मनरेगा दिवस के जॉच से संबंधित प्रतिवेदन google doc. पर अद्दतन कराने का निर्देश दिया गया है । मनरेगा के अंतर्गत सभी लंबित भुगतान को Clear करने का निर्देश दिया गया ।

जिले के द्वारा यह बताया गया कि द्वितीय किस्त की राशि के लिए केन्द्र द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है । यह निर्देश दिया गया कि कैम्प कराकर अवशेष लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाय ।

बक्सर:- जिला के द्वारा यह बताया गया कि शत-प्रतिशत श्रम बजट अपलोड किया जा चुका है एवं Realistic Labour Budget तीन दिनों के अंदर अपलोड कर लिया जायगा । मनरेगा कर्मियो के सम्पति का व्यौरा बेवसाइट पर अपलोड किये जाने की सूचना भी दी गयी ।

इंदिरा आवास अंतर्गत सभी लाभार्थियों का खाता बैंक मे खुलवाये जाने की सूचना जिले के द्वारा दी गयी ।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अंतर्गत जिले के द्वारा यह बताया गया की भेंडर के द्वारा डाटा NIC के सर्वर पर अपलोड नही किया जा रहा है । 150 टैबलेट पी0 सी0 की मांग जिले के द्वारा की गयी ।

पटना :-पटना जिला के द्वारा यह बताया गया कि शत-प्रतिशत वास्तविक श्रम बजट अपलोड किया जा चुका है। मनरेगा कर्मियो का 6 माह से भुगतान लंबित रहने की सूचना दी गयी । यह

निर्देश दिया गया की लंबित मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र करते हुए पूर्व के वित्तीय वर्ष का भी लंबित भुगतान कर दिया जाय ।

गया :- जिला के द्वारा यह बताया गया कि शत-प्रतिशत वास्तविक श्रम बजट अपलोड किया जा चुका है । दिनांक 16.01.2013 तक मनरेगा दिवस जॉच का प्रतिवेदन goole doc पर अपलोड कर दिया गया है । यह निर्देश दिया गया की लंबित मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र करते हुए पूर्व के वित्तीय वर्ष का भी लंबित भुगतान कर दिया जाय ।

जिले के द्वारा बताया गया इंदिरा आवास योजना अंतर्गत वास स्थल मद की 4 (चार) करोड रूपये में से 39 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है । यह निर्देश दिया गया कि 39 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हुए अवशेष राशि को इंदिरा आवास योजना में लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं राशि हस्तांतरित किये जाने की सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दी जाय।

बेगुसराय:- जिला के द्वारा यह बताया गया कि Realistic Labour Budget तीन दिनों के अंतर्गत अपलोड कर दिया जायेगा । जिले को यह निर्देश दिया गया की मनरेगा कर्मियों को लंबित मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय ।

जिले के द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास अंतर्गत दिनांक 19.02.2013 को विशेष कैंप का आयोजन किया जायेगा ।

इसी प्रकार शेष सभी जिलो को आरंभ में दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए विडियो कांफ्रेंसिंग की कार्रवाई समाप्त की गयी ।

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ज्ञापांक ग्रा॰वि॰ अनु॰ को – 18/2013 पटना, दिनांक ____________

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकरी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित ।

C:\Users\ADMIN\Desktop\कार्यवाही 08.02.2013.docx